



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2090]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936

No. 2090]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2635(अ).—वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री एस नटराजन, उपाध्यक्ष, वी. ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन की अध्यक्षता में लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित किए जा रहे संघ क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले पोतों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मियों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एक-एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करती है।

2. उपर्युक्त न्यायाधिकरण को नौवहन महानिदेशालय, मुंबई की कर्मिंदल शाखा द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।

3. उपर्युक्त न्यायाधिकरण भेजे गए मामले का निपटान तेजी से करेगा एवं कार्यवाहियों के समाप्त होने पर फैसला केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. एसएस-14017/2/2013-एस वार्ड. II]

सी. बी. सिंह, सलाहकार

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2014

S.O. 2635(E).—In exercise of the powers conferred by Section 150(1) of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby constitutes a One Person Tribunal under Shri S. Natarajan, Deputy Chairman, V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin for adjudicating the dispute between officers and crews in the ships owned by Union Territory of Lakshadweep Administration (UTLA) being operated by the Lakshadweep Development Corporation Limited (LDCL).

2. The Tribunal will be serviced by the Crew Branch of Directorate General of Shipping, Mumbai.

3. The Tribunal shall dispose of the reference expeditiously and on the conclusion of the proceedings, submit its award to the Central Government.

[F. No. SS-14017/2/2013-SY.II]

C.B. SINGH, Advisor